

202

संख्या: 473/उन्तीस(2)/12-2(39पे0)/201

प्रेषक,

जी0 बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 28 सितम्बर, 201

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी की दोड़म ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या 70/ DP (IV)/2012-13 दिनांक 27-04-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौलादेवी की दोड़म ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के अनुमानित लागत ₹ 859.97 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 विस्तार परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 702.84 में से ₹ 78.09 लाख (सेन्टेज 11.11% धनराशि) को कम करते हुए शेष धनराशि ₹ 624.75 लाख इसी प्रकार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत संस्तुत धनराशि ₹ 95.07 लाख में से ₹ 10.56 लाख (सेन्टेज की धनराशि) को कम करते हुए शेष धनराशि ₹ 84.51 लाख के प्रकार कुल धनराशि ₹ 709.26 लाख (₹ सात करोड़ नौ लाख छब्बीस हजार दो सौ नब्बे रुपये) के अन्तर्गत संस्तुत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (I)- उक्त योजना की मात्र प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
- (II)- प्रस्तावित पम्पिंग योजना के निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पम्पिंग योजना ही अंतिम विकल्प है।
- (III)- यदि योजना में वन भूमि का हस्तान्तरण होना है तो वन भूमि विभाग के हस्तान्तरण के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
- (IV)- प्रति वर्ष माई अप्रैल, मई तथा जून में पानी का discharge लिया जाये तथा 03 अक्टूबर के न्यूनतम discharge पर योजना निर्मित की जानी चाहिए पूर्व में निर्मित योजनाओं की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उसी क्षेत्र के लिए बनायी जाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत करायें जाने वाले सिविल कार्यों को यथा आवश्यकता उनकी कार्य स्थिति के अनुरूप उपयोग किया जाये।
- (V)- पूर्व निर्मित योजनाओं के अन्तर्गत डाले गये पाईपों का उनकी भौतिक स्थिति अनुसार यथासम्भव उपयोग किया जाये। पुरानी पाईप लाईनों के उपयोग /अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में जिला स्तर पर अन्य विभागों के तकनीकी अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए Joint inspection हेतु एक समिति बनाई जाये जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्माण से पूर्व D.P.R. अथवा निर्माण के बाद यथास्थिति का समावेश किया जाये।
- (VI)- पानी की निरंतर एवं सुचारु व्यवस्था में सामान्यतः low voltage electricity की समस्या आती है इसलिए प्रत्येक नयी योजनाओं में Separate feeder की व्यवस्था D.P.R. में सम्मिलित की जाये। Low frequency की समस्या के निदान हेतु पम्पिंग प्लांट का डिजाइन Low frequency पर किया जाये।

क्रमशः 2 पेज

28-09-12

- (VII)- पेयजल आपूर्ति के लिए पम्पिंग पेयजल योजनायें दीर्घकालीन निदान नहीं हैं। दीर्घकालीन निदान के लिए योजना में ग्राम स्तर पर पूर्व में निर्मित चाल / खाल अन्य घरेलू कार्य तथा Source recharge हेतु Check dam गली प्लगिंग, storage tank, rain water harvesting आदि सार्थक एवं उपयोगी योजनायें तैयार की जायें। प्रत्येक योजना में ग्राम स्तर पर पूर्व में निर्मित चाल/खाल को पुर्नजीवित करने के कार्य को अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु शासनादेश सं. 768/रा0यो0आ0/2011, दिनांक 28-06-2011 में दिये गये निर्देशानुसार क्रियान्वयन किया जाये।
- (VIII)- ऐसी पम्पिंग योजनाएं जहां गंधरा श्रोत है वहाँ श्रोत कार्यो पर 08 घण्टे श्राव तुल्य storage tank का निर्माण कर श्रोत में उपलब्ध 24 घण्टे के श्राव को 16 घण्टे में pump किया जाये।
- (IX)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय, उत्तराखण्ड को प्राप्त होने वाली धनराशि में से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी जा रही है।
- (X)- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (XI)- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधित स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (XII)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।
- (XIII)- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- (XIV)- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (XV)- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का निरीक्षण भलीभाँति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- (XVI)- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उन्मुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- (XVII)- आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (XVIII)- स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।
- (XIX)- योजना पर सेन्टेज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- (XX)- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियम तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों के प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (XXI)- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी। कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

28.4.12

- (XXII)-व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप
नियमावली, 2008 एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।
- (XXIII)-मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2008)
दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन
करते समय कड़ाई से पालन करें।
- (XXIV)- कार्य कराने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू गठित
लिया जाय जिसमें defect liability clause का प्राविधान भी सुनिश्चित कर
जाय।
- 2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 388/XXVII(2)/2012 दिनांक 2
सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी० बी० ओली)
संयुक्त सचिव,

पृष्ठांकन संख्या: 173/उन्नीस(2)/12-2(39पे०)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमायू मण्डल।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
7. निदेशक, एनओआईसी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
12. सम्बन्धित अधिशासी अभिचन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गारिमा सैकली)
उप सचिव,